कोई कार्रवाई करेगी जिन्होंने अपने बीमा एजेंटों को इस शर्त को बताने से रोक दिया जिसके कारण हजारों लोगों का नुकसान हुआ। यह शर्त पूर्व सरकार के समय में बदली गई थी और हो सकता है कि सरकार ने जीवन बीमा निगम के उच्च अधिकारियों के ऊपर दबाव डाला हो कि वे इस तरह के आदेशों को एजेन्टों को न बतलाने को कहें, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार ने भी जीवन बीमा निगम के अधिकारियों पर ऐसा दबाव तो नहीं डाला है और यदि हमारी सरकार ने ऐसे आदेश नही दिये है तो क्या सरकार उन उच्च अधिकारियो के खिलाफ़ कार्यवाही करेगी जिन्होंने अपने एजेंटों को इस शर्त को न बताने के लिए कहा हो।

तीसरे क्या यह सही नही है कि जनता सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गयी है और गलत समाचार दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार बीमा मैनेजमेंट अधिकारियों के नेता के खिलाफ कार्यवाही करेगी अगर यह खबर गलत हो?

(ii) REPORTED LEAKAGE OF ALVA COMMISSION REPORT

SHRI BHAGAT RAM (Phillaur): With your permission, I am raising this matter of urgent public importance under rule 377: the statement of Shri Raj Narain hon. Health Minister in the Lok Sabha on 2nd March 1978 that the report of the Alva Commission has come as a "shocking revelation" on the treatment meted out to Shri Jayaprakash Narain during his detention in the PGI and the news item in the Indian Express, March 4, 1978 'PGI doctors indicated' is causing grave doubts among the people of the country about the PGI, Chandigarh. The entire nation was looking forward to see the real contents of the report which the hon. Minister promised to place on the Table of the House. But the subsequent decision of the Minister not to disclose the so-called 'interim report' to spread dissatisfaction and suspicious amongst the people. Now a news report from the *Tribune*, Chandigarh dated 12-3-1978 under the heading of 'Mystery of JP's Digoxin Toxicity not solved' has disclosed really the shocking revelations which must be probed through a judicial enquiry to clear the doubts and suspicion. The demand for a judicial enquiry as put forth by PGI doctors has a general support from all walks of life and must be conceded to so that justice prevails and the public is made aware of the facts. Only in judicial enquiry the realities can be brought to book where everybody shall have the right to say and the right to defence. In view of the above, I would like to request the hon. Minister to make a categorical statement about the leakage of report to the Press before it is presented to the Parliament and I also strongly demand a judicial enquiry into the whole incident.

(iii) SITUATION IN ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

श्री चन्द्रशेखर सिंह (वाराणसी): अध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आजमगढ़ी और गैरआजमगढ़ी स्थिति से उत्पन्न अशांत और उपद्रवग्रस्त वातावरण की ओर सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं।

वहां के वाइस चांसलर ने विश्वविद्यालय को दो भागों में विभक्त कर दिया है—एक तो आजमगढ़ी और दूसरा गैरआजमगढ़ी। आजमगढ़ी से उनका मतलब यह है कि अलीगढ़ से पूर्व के जो भी विद्यार्थी है वे आजमगढ़ी है। इस सम्बन्ध में वहां के एक विद्यार्थी, श्री अमजदखां जो कि सुलेमान हाल मे रहते हैं, ने जब वाईस चांसलर से इस बारे में पूछा तो उन्होंने भी यह बताया कि आजमगढ़ी मीस अलीगढ़ यूनीवर्सिटी से पूर्व और बिहार के बार्डर तक का क्षेत्र। इस स्थिति के चलते वहां के विद्यार्थियों के संगठन ने, अध्यापक संगठन ने, कर्मचारियों के संगठन ने वहां के वाइस चांसलर को वहां से हटाने की मांग की है। स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि इस भ्रष्टाचार,

[श्री चन्द्रशेखर सिंह]

अनाचार और दुराचार के खिलाफ़ वहां एक जेहाद-सा छिड गया है। आजमगढ़ी और गैर आजमगढ़ी की तिकड़म करके वहां के वाइस चासलर ने आजमगढ़ी लडको को पिटवाया, जिसके कारण लडकों के सिर टूटे, पैर टूटे और हाथ टूटे। स्थिति बहुत भयकर बनती चली जा रही है। अलीगढ से पूर्व के जो विद्यार्थी है उन मे से 28 को निष्कासन कर दिया गया है और यह निष्कासन बिना अनुशासन समिति की सिफारिश के किया गया है। यह हालत वहा बनती चली जा रही है। आज विश्वविद्यालय दो गुटो मे पूरा का पूरा विभक्त हो चुका है। लखनऊ, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती यह सब तो आजमगढ़िया इलाका है, जो बिहार के बोर्डर से सटा हुआ है, यहा के लोग आजमगढी इलाके के हैं और उनके साथ वहा का वाइस चासलर सौतेला व्यवहार कर रहा है। इस तरह के व्यवहार के चलते वहा के विद्यार्थियो के लिए वहा रहना दुभर हो गया है। अस्त व्यस्त, त्रस्त, घोर आपदा ग्रस्त और उपद्रवग्रहस्त, ऐसी स्थिति मे वहा वाइस चासलर के रहते बनती चली जा रही है। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। वहा विद्यार्थियो की माग है कि वाइस चासलर को तुरन्त हटाया जाए। मैं चाहता हू कि सरकार इस ओर ध्यान दे और तत्काल कोई प्रभावकारी कार्य करे।

(IV) LIKELIHOOD OF LOCUST INVASION

श्री नाथू सिंह (दौसा) नियम 377 के तहत मैं इस मामले को उठा रहा हू। विश्व खाद्य एव कृषि सगठन के अनुसार अफ्रीका, अरब देशो और भारतीय उपमहाद्वीप मे भारी टिड्डी दलो के हमले की आशंका उत्पन्न हो गई है। पता चला है कि अरबो की सख्या में टिड्डियो के दल अफ्रीकी देशो मे प्रविष्ट हो रहे हैं। टिड्डियों की सख्या एक किलोमीटर मे चालीस हजार लाख से ले कर आठ हजार लाख तक होती है। 1958 मे टिड्डियों के इन दलों ने हमारे यहां 1.67 लाख टन अनाज नष्ट कर दिया था।

स्वतन्त्रता के बाद चीन और पाकिस्तान ने ही हमारे देश पर हमला नही किया, कई बार इन टिड्डी दलो ने भी किया जिससे लाखो टन अनाज की क्षति हुई। इसके बारे मे मैं सरकार को सतर्क करना चाहता हूं, मत्री महोदय को सतर्क करना चाहता हूं और चाहता हू कि वह ऐसी व्यवस्था करे ताकि ये टिड्डी दल हमारे देश की सीमाओ मे प्रविष्ट न हो सकें और उनके द्वारा नष्ट होने वाले अनाज को बचाया जा सके। यदि ऐसा नही किया गया तो देश को जो भारी क्षति होगी उससे बचा नही जा सकेगा।

(V) SERIOUS SITUATION IN PATNA

श्री मनोहर लाल (कानपुर) 377 के अधीन मैं आपका तथा इस माननीय सदन का ध्यान दिलाते हुए पटना मे जो विस्फोटक स्थिति पैदा होती जा रही है उसकी ओर ध्यान खीचना चाहता हू। काग्रेस ने शुरू से ही डिवाइड एंड रूल की नीति का अवलम्बन किया था। इस नीति का अवलम्बन करने मे इसने 30 साल तक ज़रा भी सकोच नही किया। गद्दी से हटने के बाद भी वह खुलेआम इसी नीति पर चल रही है। आपने जैसा अखबारो मे देखा होगा कि श्री जयप्रकाश नारायण के अमृत महोत्सव पर भी जातिवाद का नारा लगाया गया और कुछ अशोभनीय घटनाएं की गई। श्री जगजीवन राम के साथ वहा के मुख्य मत्री श्री कर्पूरी ठाकुर के साथ भी इसी तरह का अभद्र व्यवहार किया गया है। अराजक तत्वो के साथ इन लोगो ने मिल कर इस तरह की घटनाए वहां पर कराई हैं। काका कालेलकर की अध्यक्षता मे बने कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी जिसमे बैकवर्ड क्लासिस के लोगो के लिए तरह तरह की सुविधाए देने की सिफारिश की गई थी। लेकिन आज तक हमारी कांग्रेस की सरकार ने जब तक वह सत्ता मे रही इस रिपोर्ट को कार्यरूप मे परिणत नही किया। आज जब जनता पार्टी की सरकार